



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]
No. 233]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 6, 2006/आश्विन 14, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2006/ASVINA 14, 1928

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2006

सं. 5/2/2006-संस्था-III (क).—भारत सरकार विगत सरकारी कर्मचारियों को परिलब्धियों में होने वाले ढांचागत परिवर्तनों पर पिछले कुछ समय से विचार करती रही है। वर्ष 1997 में, पिछले वेतन आयोग द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट के बाद से परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन भी हुए हैं। तदनुसार, नीचे दर्शाई गई संरचना के अनुसार छठा केन्द्रीय वेतन आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है:—

1.	अध्यक्ष	—	न्यायमूर्ति श्री बी. एन. श्रीकृष्ण
2.	सदस्य	—	प्रो. रविन्द्र ढोलकिया
3.	सदस्य	—	श्री जे. एस. माथुर
4.	सदस्य-सचिव	—	श्रीमती सुषमा नाथ.
2.	आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:—		

(क) कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं/लाभों, भले ही वे नकद रूप में हों या वस्तुगत रूप में, को संरचना को शासित करने वाले सिद्धांतों तथा उनके लागू होने की तारीख की जांच करना:—

- (i) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी—औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक;
- (ii) अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक;
- (iii) रक्षा सेनाओं से संबंधित कार्मिक;
- (iv) संघ शासित क्षेत्रों के कार्मिक;
- (v) भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी; और
- (vi) संसद के अधिनियमों के अंतर्गत गठित विनियामक निकायों के अधिकारी तथा कर्मचारी;।

(ख). केन्द्रीय सरकारी संगठनों को नागरिकों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध आधुनिक व्यावसायिक दक्षता से परिपूर्ण तथा जनानुकूल निकायों में तब्दील करना;

- (ग) ऊपर 'क' में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए वेतन संचना का एक ऐसा पैकेज तैयार करना जो मितव्ययिता, जवाबदेही, दायित्व भावना, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी को अपनाने और अनुशासन को बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी दायरे में आने वाली संरचनाओं, संगठनों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में औचित्य स्थापित करते हुए, सरकारी कर्मचारियों की दक्षता, उत्पादकता और अर्थव्यवस्था वृद्धि के साथ कारगर तरीके से जुड़ा हुआ हो ;
- (घ) उभरते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की मांगों के अनुरूप केन्द्रीय सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन में सामंजस्य लाना। इसमें अन्य प्रासांगिक तथ्यों यथा-कर्मचारियों के लिए उपलब्ध लाभों की समग्रता, तर्क-संगति की आवश्यकता और उसका सरलीकरण, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध मौजूदा वेतन ढांचे तथा सेवानिवृत्ति लाभों, देश की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में राजकोषीय विवेक के इस्तेमाल की आवश्यकता, केन्द्र सरकार के संसाधन तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कारण इसकी मांगों, रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वभौमिक परिदृश्यों तथा राज्यों द्वारा सिफारिशों को अपनाए जाने की स्थिति में राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखा जाएगा;
- (ङ) 01 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त हुए मौजूदा तथा पूर्व केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर वित्तीय निहितार्थों के साथ उन सिद्धान्तों का निरीक्षण करना जो पेंशन के ढांचे, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य आवधिक अथवा आवर्ती लाभों को शासित करें;
- (च) सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय पैरामीटरों (प्राचलों) और परिस्थितियों के संबंध में सिफारिश करना जो विभिन्न विभागों में मौजूदा तदर्थ बोनस स्कीम के स्थान पर बोनस के भुगतान तथा उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीमों को शुरू करने की वांछनीयता और व्यवहार्यता को शासित करे तथा उत्पादकता सूचकांक तथा अन्य संबंधित पैरामीटरों को निर्धारित करने वाले विशिष्ट फार्मूलों की सिफारिश करना;
- (छ) आयोग द्वारा सिफारिशों करने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने में लगने वाले समय के लिए किसी अंतरिम राहत की वांछनीयता और स्वीकृति की आवश्यकता की जांच करना।

3. आयोग अपनी स्वयं की कार्यविधि तैयार करेगा और यह सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकेगा, जिन्हें वह किसी विशेष प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे। वह ऐसी सूचना मांग सकता है और ऐसा साक्ष्य ले सकता है जिसे वह आवश्यक मान जाए। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग ऐसी सूचना और दस्तावेज तथा अन्य तरह की सहायता प्रस्तुत करेंगे जिनकी आयोग द्वारा मांग की गई हो। भारत सरकार को यह विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संबंधी एसोसिएशन और अन्य संबंधित पक्ष; आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

4. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

5. आयोग अपनी सिफारिशों अपने गठन की तारीख से 18 माह के भीतर प्रस्तुत करेगा। आयोग, यदि आवश्यक समझे, तो किसी भी विषय पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिए जाने पर ही उससे संबंधित रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है।

आदर्श किशोर, वित्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th October, 2006

No. 5/2/2006-E.III(A).—The Government of India have been considering for some time past the changes that have taken place in the structure of emoluments of Government employees over the years. Conditions have also changed in several respects since the last Pay Commission made its Report in 1997. Accordingly, it has been decided to appoint the Sixth Central Pay Commission comprising of the following :—

1. Chairman	—	Mr. Justice B. N. Srikrishna
2. Member	—	Prof. Ravindra Dholakia
3. Member	—	Shri J.S. Mathur
4. Member-Secretary	—	Smt. Sushama Nath

2. The terms of reference of the Commission will be as follows :—

- (A) To examine the principles, the date of effect thereof, that should govern the structure of pay, allowances and other facilities / benefits, whether in cash or in kind, to the following categories of employees :—
 - (i) Central Government employees—Industrial and non-Industrial;
 - (ii) Personnel belonging to the All India Services;
 - (iii) Personnel belonging to the Armed Forces;
 - (iv) Personnel of the Union Territories;
 - (v) Officers and employees of the Indian Audit and Accounts Department; and
 - (vi) Officers and employees of the regulatory bodies set up under Acts of Parliament.
- (B) To transform the Central Government Organisations into modern, professional and citizen-friendly entities that are dedicated to the service of the people.
- (C) To work out a comprehensive pay package for the categories of Central Government employees mentioned at (A) above that is suitably linked to promoting efficiency, productivity and economy through rationalization of structures, organisations, systems and processes within the Government, with a view to leveraging economy, accountability, responsibility, transparency, assimilation of technology and discipline.
- (D) To harmonize the functioning of the Central Government Organisations with the demands of the emerging global economic scenario. This would also take in account, among other relevant factors, the totality of benefits available to the employees, need of rationalization and simplification thereof, the prevailing pay structure and retirement benefits available under the Central Public Sector Undertakings, the economic conditions in the country, the need to observe fiscal prudence in the management of the economy, the resources of the Central Government and the demands thereon on account of economic and social development, defence, national security and the global economic scenario, and the impact upon the finances of the States if the recommendations are adopted by the States.
- (E) To examine the principles which should govern the structure of pension, death-cum-retirement gratuity, family pension and other terminal or recurring benefits having financial implications to the present and former Central Government employees appointed before January 1, 2004.
- (F) To make recommendations with respect to the general principles, financial parameters and conditions which should govern payment of bonus and the desirability and feasibility of introducing Productivity Linked Incentive Scheme in place of the existing *ad hoc* bonus scheme in various Departments and to recommend specific formulae for determining the productivity index and other related parameters.
- (G) To examine desirability and the need to sanction any interim relief till the time the recommendations of the Commission are made and accepted by the Government.

3. The Commission will devise its own procedure and may appoint such Advisers, institutional consultants and experts, as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence, as it may consider necessary. Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission. The Government of India trusts that State Governments, Service Associations and others concerned will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance.

4. The Commission will have its headquarters in Delhi.

5. The Commission will make its recommendations within 18 months of the date of its constitution. It may consider, if necessary, sending reports on any of the matters as and when the recommendations are finalized.

ADARSH KISHORE, Finance Secy.